आयकर ने खोलीं संदिग्ध धन की परतें

394 संस्थाएं और 36 पेशेवर जांच के घेरे में, सीमा से लगे राज्यों की 117 इकाइयों पर भी नजर

नई दिल्ली, 19 अगस्त कम या शून्य कारोबार दिखाकर विदेशों में बड़ी रकम भेजने वाली संस्थाएं अब आयकर विभाग के रडार पर हैं. विभाग ने संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण के मामलों में देशव्यापी सत्यापन अभियान शुरू किया है.

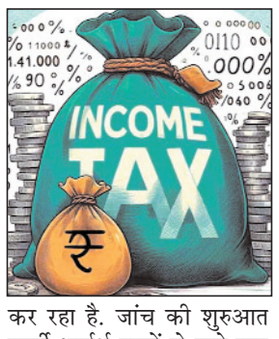

पिछले तीन वर्षों के विदेशी धन प्रेषण से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण और जमीनी स्तर से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसी कई संस्थाओं की पहचान की गई है, जिनका घोषित कारोबार विदेश भेजी गई रकम के मुकाबले बेहद कम था. अब विभाग इन संस्थाओं के वास्तविक कारोबार, धन के स्रोत और विदेश में रकम प्राप्त करने वालों के बीच संबंधों की जांच कर रहा है. जांच की शुरुआत फर्जी धर्मार्थ ट्रस्टों से जुड़े एक नेटवर्क की पड़ताल से हुई.

विभाग को ऐसे ट्रस्टों के बारे में जानकारी मिली, जो कथित तौर पर फर्जी दान और योगदान के बदले बोगस एंट्री उपलब्ध कराने में शामिल थे. इस कार्रवाई के दौरान विदेशों में धन भेजने वाली कुछ संस्थाओं से जुड़े सुराग मिले. इसके बाद विभाग ने पिछले तीन वर्षों के विदेशी धन प्रेषण के आंकड़ों का विश्लेषण किया और संदिग्ध संस्थाओं को चिन्हित किया प्रारंभिक सत्यापन में कई संस्थाएं ऐसी मिलीं, जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था. वहीं, कुछ संस्थाओं ने बेहद कम कारोबार घोषित किया. इसके बावजूद उनके बैंकिंग लेनदेन में विदेशों को बड़ी रकम भेजे जाने की जानकारी मिली. विभाग के अनुसार, घोषित कारोबार और विदेश भेजी गई रकम के बीच कोई स्पष्ट आर्थिक संबंध नहीं मिला.

जांच में विदेशी भुगतान के लिए बताए गए कारण भी सवालों के घेरे में हैं. कई संस्थाओं ने माल ढुलाई, सॉफ्टवेयर आयात और परामर्श सेवाओं के भुगतान का हवाला दिया. हालांकि, उनकी वित्तीय स्थिति इन बड़े विदेशी भुगतानों से मेल नहीं खाती थी.

> सीबीडीटी ने कहा है कि फॉर्म 15सीबी या फॉर्म 146 जारी करने वाले अकाउंटेंट को संबंधित लेनदेन और दस्तावेजों की पर्याप्त जांच के बाद ही प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए. उन्हें उचित सावधानी और पेशेवर निर्णय के साथ प्रमाणन करना होता है. विभाग अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटा है. सत्यापन के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

आईपीओ की शानदार लिस्टिंग, 35% प्रीमियम

मुंबई, 19 अगस्त शिपरॉकेट के शेयरों ने बुधवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की. 1,617.5 करोड़ रुपये का आईपीओ 99.38 गुना सब्सक्राइब होने के बाद करीब 35 प्रतिशत प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ. कंपनी के शेयर एनएसई पर 131 रुपये और बीएसई पर 129.50 रुपये पर सूचीबद्ध हुए, जबकि आईपीओ का ऊपरी मूल्य बैंड 97 रुपये प्रति शेयर था.

इस तरह एनएसई पर निवेशकों को प्रति शेयर 34 रुपये की शुरुआती बढ़त मिली. आईपीओ 12 से 14 अगस्त तक खुला था और निवेशकों की ओर से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) का हिस्सा 122.80 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 88.99 गुना और खुदरा निवेशकों का हिस्सा 46.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

कंपनी ने आईपीओ के जरिये 1,617.5 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसमें 885.5 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 731.9 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश शामिल है. कंपनी नई पूंजी का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार, कर्ज चुकाने और अन्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी.

भारत-जापान साझेदारी से यूपी में निवेश-रोजगार बढ़ेगा

200 से ज्यादा जापानी कारोबारी पहुंचे भारत

21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य निवेश बैठक

नई दिल्ली, 19 अगस्त उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी उद्योगपतियों से निवेश बढ़ाने पर चर्चा की. दिल्ली के ताज होटल में आयोजित इंडिया-जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का न्योता दिया.

उन्होंने कहा कि भारत-जापान की मजबूत साझेदारी को उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों में बदला जाएगा. यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 200 से अधिक जापानी सीईओ और कारोबारी प्रतिनिधियों का दल भारत पहुंचा है. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत-जापान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं.

राज्य सरकार जापानी निवेशकों को परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हरसंभव सहयोग देगी. यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने भी उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और निवेश के माहौल की सराहना की. जापानी प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग में रुचि दिखाई.

> इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत कई मंत्री मौजूद रहे. 18 से 23 अगस्त तक चल रहे यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट के तहत 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य निवेश बैठक होगी. इसमें सरकार और कारोबारियों के बीच संवाद के साथ कारोबार-से-कारोबार बैठकें होंगी. 22 अगस्त को जापानी प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचेगा.

अहमदाबाद से भागलपुर अब हर दिन चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

अहमदाबाद, 19 अगस्त. पश्चिम रेलवे द्वारा 09447/09448 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद साप्ताहिक क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए ट्रेन संख्या 19423/19424 अहमदाबाद-भागलपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा.

ट्रेन संख्या 19423 की नियमित सेवा 26 अगस्त 2026 से तथा ट्रेन संख्या 19424 की नियमित सेवा 28 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी. ट्रेन संख्या 19423 अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से 18:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा शुक्रवार को 06:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 19424 भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से 16:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा रविवार को 05:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

प्रमुख ठहराव

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर तथा सुल्तानगंज स्टेशनों पर ठहरेगी.

सीतारमण के नेतृत्व में भारत-सिंगापुर आर्थिक संवाद

19-20 अगस्त को सिंगापुर में होगा चौथा मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन

जयशंकर, पीयूष गोयल और जितिन प्रसाद भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल

नई दिल्ली,19 अगस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भारत-सिंगापुर आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए सिंगापुर पहुंचा है. प्रतिनिधिमंडल चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगा.

दो दिवसीय यह बैठक 19 और 20 अगस्त को आयोजित की जा रही है. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना, मौजूदा सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना और नए क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं तलाशना है. प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल हैं. भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय आर्थिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच है. इसकी स्थापना 2022 में की गई थी. इस मंच के माध्यम से दोनों देश व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं.

> इस बार सम्मेलन में छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. इनमें उन्नत विनिर्माण, संपर्क व्यवस्था और डिजिटलीकरण प्रमुख हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है. भारत और सिंगापुर इन क्षेत्रों में तकनीक, निवेश और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के जरिए सहयोग को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं. उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से नई तकनीकों और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है. वहीं डिजिटलीकरण और संपर्क व्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

आधार में ईमेल अपडेट करना हुआ आसान

नई दिल्ली, 19 अगस्त आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए अब लोगों को लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. दी गई जानकारी के अनुसार, आधार ऐप के माध्यम से घर बैठे ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है. इसके लिए उपयोगकर्ता को मोबाइल में आधार ऐप डाउनलोड कर प्रोफाइल बनानी होगी. इसके बाद 'आधार डिटेल्स अपडेट' विकल्प के जरिए ईमेल आईडी बदलने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. नई ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद जरूरी प्रमाणीकरण और सत्यापन पूरा करना होगा.

सेमीकंडक्टर सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट

12 परियोजनाओं को मंजूरी, तीन में शुरू हो चुका है वाणिज्यिक उत्पादन

छह देशों और 10 राज्यों के पवेलियन बनेंगे आयोजन का आकर्षण

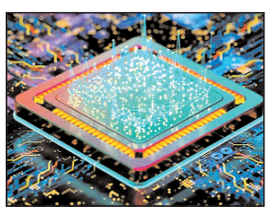

नई दिल्ली, 19 अगस्त भारत के तेजी से उभरते सेमीकंडक्टर क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में 'सेमीकॉन इंडिया 2026' के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे.

'सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' थीम पर आधारित इस सम्मेलन और प्रदर्शनी में दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनियों, नीति-निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप्स और छात्रों की भागीदारी होगी. आयोजन का उद्देश्य भारत में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने के साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की भूमिका को मजबूत करना है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और वैश्विक उद्योग संगठन सेमी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास, विनिर्माण, डिजाइन, अनुसंधान, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.

शेयर बाजार में गिरावट जारी

326 अंक पर टूटा सेंसेक्स

76.6 अंक पर फिसला निफ्टी

मुंबई, 19 अगस्त घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहा. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के दबाव के बीच दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए.

सेंसेक्स 325.78 अंक टूटकर 76,909.68 अंक पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी-50 सूचकांक 76.60 अंक फिसलकर 24,078.30 अंक पर आ गया. बाजार में निवेशकों की सतर्कता का असर कारोबार के दौरान भी देखने को मिला. प्रमुख क्षेत्रों के शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार पर दबाव बना रहा. विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक बाजारों की दिशा, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और आगामी आर्थिक संकेतकों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है. कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में ही खरीदारी को प्राथमिकता दी.

100 से ज्यादा उद्योगपतियों से मिले भूपेंद्र पटेल

अहमदाबाद, 19 अगस्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 100 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बैठकें कीं. राउंड टेबल और आमने-सामने हुई चर्चाओं में गुजरात को निवेश के गंतव्य के बजाय प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में पेश किया गया.

पटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी, गेमिंग और डीपटेक से जुड़े कारोबारियों के साथ निवेश, शोध, कौशल विकास और कारोबारी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की. उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को जनवरी 2027 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने का न्योता भी दिया.

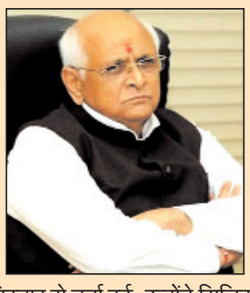

> मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात में अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए जमीन, बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी, पूंजी, प्रतिभा और स्थिर नीतियों समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को लेकर भी कंपनियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने सिलिकॉन वैली की तकनीकी क्षमता को गुजरात के मजबूत औद्योगिक आधार से जोड़ने पर जोर दिया.

समाचार विशेष

परिषद के माध्यम से जेन-जी कनेक्ट अभियान

भाजपा ने जेन-जी और जेन अल्फा से जुड़ने की बनाई नई रणनीति

नई दिल्ली. परीक्षाओं में अनियमितताएं होती जा रही थीं और छात्रों के बीच इसे लेकर नाराजगी घर करती जा रही थी. कॉकरोच जनता पार्टी को मंच मिला तो छात्रों की भावनाओं ने आंदोलन का रूप ले लिया.

यह दूसरा पहलू हो सकता है कि इस आंदोलन को प्रचारित करने के पीछे क्या राजनीतिक और तकनीकी हथकंडे थे, लेकिन भाजपा अब इसे लेकर जरूर गंभीर चिंतन में है कि पहले की तुलना में कहीं अधिक मुखर इस किशोर पीढ़ी के मुद्दों और भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

चिंता इसे लेकर भी है कि बागी बालमन को भटका कर कोई संगठन राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर न पाए, इसलिए भाजपा के आनुषांगिक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जेन-जी कनेक्ट अभियान चलाया जाएगा. इस पीढ़ी को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ना नहीं, बल्कि न्यूनतम आयु वर्ष की सीमा को और घटाकर इस पीढ़ी के बीच सक्रिय संवाद शुरू किया जाएगा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामान्यत: डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अधिक सक्रियता से काम करता है. छात्र राजनीति और रचनात्मकता की गतिविधियों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों को जोड़ता है.

सिर्फ संवाद से मुद्दों पर बात

भाजपा के शीर्ष नेता इस मंथन में जुटे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अब नौवीं कक्षा के स्कूली छात्रों या कोचिंग संस्थाओं में भी सक्रिय किया जाए. कुछ ऐसी कार्ययोजना का विचार है कि इन छात्रों को संगठन की गतिविधियों से न जोड़ते हुए सिर्फ संवाद कर इनके मुद्दों पर बात की जाए. उनके माध्यम से पार्टी और सरकार तक फीडबैक आए और उनके मुद्दों का हल नीतियों-योजनाओं में दिखाई पड़े तो उसका संदेश भी व्यवस्थित माध्यम से उन तक पहुंचे. उल्लेखनीय है कि अब जेन-जी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंटरनेट मीडिया से संबोधित कर रहे हैं. पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने भी जेन-जी के साथ संवाद किया.

परिसीमन पर संख्या पूरी नहीं हो रही

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने विवादित एफसीआरए बिल टाल दिया है. फिर भी ऐसा लग रहा है कि परिसीमन के मसले पर सरकार विपक्ष का समर्थन नहीं हासिल कर पा रही है और न उसकी दो तिहाई संख्या पूरी हो रही है.

माना जा रहा था कि विपक्ष इसके बाद बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा. असल में भाजपा के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही थीं कि एफसीआरए बिल मोलभाव के हथियार की तरह इस्तेमाल होगा. सरकार इसे टाल देगी तो विपक्ष नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन और परिसीमन के मसले पर मान जाएगा. यह भी कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो सरकार उसे अलग थलग कर देगी.

सरकार के संसदीय प्रबंधकों और भाजपा नेताओं की ओर से बताया जा रहा था कि अब दो तिहाई की संख्या पूरी होने ही वाली है. तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसद एनडीए के साथ आ गए हैं तो उद्धव ठाकरे के भी छह सांसद साथ आ गए हैं.

बसपा के ब्राह्मण चेहरे हुए बेगाने

2027 में मायावती कैसे साधेंगी दलित-ब्राह्मण समीकरण?

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 2007 के विधानसभा चुनाव में दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए यूपी में सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सामने उस सामाजिक गठजोड़ को फिर से मजबूत करने की चुनौती है.

पिछले कुछ वर्षों में बसपा के कई प्रमुख ब्राह्मण चेहरे पार्टी से अलग हुए या निष्कासित किए गए हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मायावती पुराने चेहरों के आभाव के बीच ब्राह्मण समाज और अन्य सामाजिक समूहों को साथ लेकर नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगी.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2007 में बसपा की सत्ता में वापसी में ब्राह्मण मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन महत्वपूर्ण रहा था. उस समय पार्टी ने दलित आधार के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़कर व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था. अब पार्टी के सामने चुनौती केवल नए ब्राह्मण चेहरों को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि समाज के बीच पुराने भरोसे को दोबारा कायम करने की भी है.

भरोसा बनाए रखने की चुनौती- वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि बसपा के सामने इस समय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भरोसा बनाए रखने की चुनौती है. हाल ही में अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया गया है. इससे पहले राकेशधर त्रिपाठी, रंगनाथ मिश्रा, रामू द्विवेदी, कुशल तिवारी, विनय शंकर तिवारी, ब्रजेश पाठक और गुड्डू त्रिपाठी जैसे कई प्रमुख ब्राह्मण चेहरे बसपा से अलग हो चुके हैं. रामवीर उपाध्याय का परिवार भी बसपा की राजनीति में सक्रिय रहा है. इनमें से कई नेता बाद में दूसरे राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दिए और कुछ को मंत्री पद भी मिला.

क्या कहा मायावती ने?

मायावती ने कहा कि ऐसे कई लोगों ने बसपा सरकार के दौरान भी अपने निजी और पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दी और पार्टी तथा समाज के हित में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई. मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी में लंबे समय से ईमानदार और निष्ठावान वरिष्ठ नेता नए कर्मठ एवं समर्पित कार्यकर्ताओं, खासकर युवाओं को तैयार कर रहे हैं. पार्टी की यह 'नर्सरी' लगातार जारी है और नए लोगों को संगठन में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है.

विशेष | मिशन 2027 : कमज़ोर जिलों के लिए खास रणनीति

भाजपा का प्लान-डैमेज कंट्रोल

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब लगभग 5 महीने बचे हैं. 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के चुनाव के लिहाज से ये वक़्त बहुत कम है. ऐसे में राजनीतिक दलों ने जमीन पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

सत्ता में बैठी बीजेपी के सामने ना सिर्फ सत्ता बचाने की चुनौती है, बल्कि 2017 के प्रदर्शन को दोहरा कर ये संदेश देने की चुनौती भी है कि 10 सालों की सत्ता के बावजूद आम जनता में बीजेपी को लेकर नाराजगी नहीं है. इसी वजह से पार्टी आंकड़ों के आधार पर जमीन पर तैयारी में जुटी है.

बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए उन जिलों की सूची बनाकर प्लानिंग शुरू की है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पार्टी ने ऐसे चार मंडल पर ज़्यादा फोकस शुरू किया है, जहां उसे अपेक्षित जीत हासिल नहीं हुई थी. ये चार मंडल आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद हैं. बीजेपी नेतृत्व ने तय किया है कि इन चार मंडलों में आने वाली विधानसभा सीटों पर खास रणनीति के तहत काम किया जाएगा. बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी ने इन चार मंडलों में आने वाले 16 जिलों की उन सीटों पर ख़ास रणनीति के तहत काम शुरू किया है, जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.

पार्टी ने मंत्रियों, बड़े नेताओं, चर्चित चेहरों और संगठन से जुड़े लोगों के विशेष दौरे और प्रवास लगाने का फैसला किया है. पार्टी स्थानीय संगठन से वहां के मुद्दों, समस्याओं और पार्टी को लेकर उनके मत से जुड़ी जानकारी ले रही है. वर्तमान में चल रहे मुद्दों को लेकर जनता का रुख़ समझने की भी कोशिश की जा रही है.

अयोध्या मंडल में कुल पांच जिले हैं. इनके अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी ज़िले शामिल हैं. आज़मगढ़ मंडल में आज़मगढ़, बलिया और मऊ ज़िले आते हैं. मुरादाबाद मंडल में आने वाले ज़िलों में मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और संभल हैं. इसी तरह सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली ज़िले आते हैं. बीजेपी इन चार मंडलों में आने वाले 16 ज़िलों की स्थिति का आंकलन कर अपनी स्थिति ठीक करने पर फोकस कर रही है.

कहां किसे कितनी सीटें मिली थीं?

बीजेपी और सपा गठबंधन के प्रदर्शन को ज़िलों के आधार पर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 में से सभी 10 सीटें सपा के खाते में गई थीं. बलिया में 7 में चार पर सपा, दो पर बीजेपी और एक पर बीएसपी को जीत मिली थी. मऊ की 4 में से एक पर बीजेपी और तीन पर सपा जीती. अयोध्या की पांच में सभी बीजेपी के खाते में गईं. अंबेडकरनगर में सभी पांच पर सपा ने बाज़ी मारी. बाराबंकी में लड़ाई बराबर की रही और सपा-बीजेपी ने तीन तीन सीटों पर विजय हासिल की. सुल्तानपुर में 5 में चार पर बीजेपी और एक सपा को मिली. अमेठी में 4 में लड़ाई बराबरी की रही.